Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa are the party States in respect of disputes relating to the Godavari Basin while Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan are concerned with the Narmada Water Dispute. The disputes relating to the Narmada and Godavari waters are at present before the Tribunals for adjudication.

Seven major and one medium irrigation schemes are in the Basins common to Bihar and West Bengal. An official level understanding for these projects which are in the Ajoy, Mahananda, Subarnarekha and Damodar Basins has been reached. This is being examined in consultation with the State Governments as it involves the use and development of Damodar Waters which is under the purview of the Damodar Valley Corporation under the Damodar Valley Corporation Act, 1948 and impinges on the provisions of the Act.

Five major and five medium projects are in the Yamuna Basin. Availability and sharing of waters of the Yamuna are being examined in consultation with the State Governments of Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Delhi Administration.

Clearance of Thein Dam Project across the Ravi is pending for a decision with regard to the sharing of costs and power benefits. The matter is being pursued with the concerned State Governments of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan.

Bahuda Stage-II Project of Orissa in the Bahuda Basin which is common to the States of Andhra Pradesh and Orissa is under discussions between the Officers of the two States.

Attempts are being made to resolve all the disputes except those relating to Narmada and Godavari by mutual discussions.

उत्तर प्रवेश में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता

4704. श्री राम लाल राही: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि वर्ष 1977-78 के लिए उत्तर प्रदेश को सिंचाई हेतु दिये जाने वाले ग्रनुदान में से राजकीय नलकूषों पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): प्रचलित पढ़ित के श्रनुसार वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य योजना स्कीमों के लिये ऋण श्रीर अनुदान के रूप में एक मुक्त रकम के तौर पर दी जाती है श्रीर इसका किसी विशेष योजना अथवा विकास के शीर्ष से कोई संबंध नहीं होता।

वर्ष 1977-78 के लिए राज्य की योजना में उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप कार्यक्रम के लिए 25.40 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

बीजों का विकास ग्रीर उनकी मांग

4705. श्री रामघारी शास्त्री: क्या कृषि ग्रीर सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने कितनी मात्रा में श्रौर कितनी किस्मों के विभिन्न बीजों का विकास किया ;
- (ख) वर्ष 1977-78 में खरीफ की फसलों के लिए किन-किन राज्यों से मांग आई है और प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी मांग की है ; श्रीर
- (ग) निगम उनकी कितनी मांग पूरी कर सकेगा ?

कृषि ग्रोर सिवाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) किस्मों का विकास करना राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है ।

Written Answers

(ख) प्रोर (ग). जिन राज्यों से राष्ट्रीय बीज

निगम को प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए पक्के मांग-पत्न मिले थे, उनके नाम, उन्हें जितनी माता में बीज देने की पेशकश की गई थी तथा बास्तव में उन्होंने कितनी माता में बीज लिए, इनसे सम्बन्धित जानकारी देने बाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खरीफ 1977-78 के लिए राज्यों से प्राप्त प्रमाणित बीजों के पक्के मांगपत्न ग्रीर उन्हें जितनी मान्ना की पेशकश की गई है और उन्होंने उसमें से कितनी मान्ना में बीज लिए।

					(f	क्वंटलों में	
क्रम राज्य का नाः सं०	म राज्यों से प्राप्त पक्के मांग पत्न फसल ग्रौर मात्रा		उपज की मात्रा		राज्य द्वारा वास्तव में उठाई गई मात्रा		
40						उठाइ गर मास्रा	
1 2	3	4	5		6	7	
1. जम्मू तथा	मक्का	गंगा एस-2	900 क्विंटल	900 वि	वंटल	900 क्विंटन	
कश्मीर	बाजरा	पी०एच०बी-14	60 ,,	60	,,	60 ,,	
		एन०एच०बी-5	22 ,,	22	"	22 ,,	
	धान	जया	125 ,,	125	,,	125 ,,	
2. पंजाब	मक्का	गंगा—5	3000 ,	3000	,,	2557 ,,	
	वाजरा	पी०एन०वी-14	1000 ,,	1000	"	510 ,,	
3. हरियाणा	वाजरा	बी ० ज ० – 1 0 4	3500 ,,	3500	,,	3417 ,,	
		पी०एच०वी-14	500 ,,	500	"	500 "	
4. मध्य प्रदेश	चरी	सी०एस०एच-5	1000 ,,	300	,,	300 ,,	
	मक्का	गंगा—5	465 ,,	400	,,	400 ,,	
		गंगा एस-2	1.00 ,,	100	,,	100 ,,	
5. म हा राष्ट्र	चरी	सी०एस०एच-5	16000 ,,	7061	"	7061 ,,	
		सी०एस०एच-1	5000 ,,	2787	,,	2787 ,,	
	धान	रतना	10000 ,,	10000	,,	2500 ,,	
6. कर्नाटक	†चरी	सी०एस०एच-1	3000 ,,	1010	,,	1010 ,,	
	-						

1	2	3	4	5	6	7
7.	त मिलना डु	धान	भ्राई०ग्रार-20	7000 क्विं	ब्ल 7000विंटवर	न े उठाई जा ेें ेरही हैं ।
			पूसा 2-21	1000 ,,	1000 ,,	}
:8.	बिहार	धान	जया	3023 ,,	3023 ,,	3023 क्विटल
			पूसा 2-21	366 ,,	366 ,,	366 ,,
			म्राई०म्रार−8	160 ,,	160 "	160 "
			रतना	160 ,,	160 ,,	160 ,,
			का वै री	40 ,,	कुछ नहीं	कुछ न हीं

†रबी 1976-77 के दौरान तुफ़ानी हवाओं के कारण रवी फसल की हुई भारी क्षंति से ग्रांध्र प्रदेश ग्रीर कर्नाटक के मुख्य उत्पादक राज्यों में चरी के उत्पादन में सामान्य कमी हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप खरीफ 1977-78 में सप्लाई में कमी ग्राई है।

Relief for Repayment of Loans to Technical Institutions

4706. SHRI P. RAJAGOPAL NAI-DU: Will the Minister of EDUCA-TION, SOCIAL WELFARE CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government Technical Institutes (including University institutions) are being given relief in the matter of repayment of Government loans for buildings; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUN-DER): (a) and (b). Interest-free loans are being given for the construction of hostels to Government, non-Government engineering and technological institutes (including University institutions) in respect of approved schemes. In view of difficulty experienced non-Government institutions (including University institutions) in the repayment of loans, it was decided, as a special case, that 50 per cent of the total loan sanctioned to the institutions

be recovered in the same number original instalments fixed and when this amount is fully repaid by the technical institutions/universities, Government of India would write off the balance of 50 per cent loan sanc-

This relief was not extended to Government institutions who did not experience any difficulty in this regard.

सरकारी क्वार्टरों का झाबंटन भ्रौर उनका किराया

4707. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या निर्माण श्रौर श्रावास तथा पूर्ति श्रौर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकारी मकानों के ब्रावंटन या किराया लेने के कितने मामलों में तत्कालीन मंत्री ने भूतपूर्व सम्पदा निदेशक की सिफारिश नहीं मानी थी:
- (ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिश न माने जाने के क्या कारण थे ;